



ग्रामीण विकास में डिजिटल इंडिया

□ डॉ० विवेक कुमार पाण्डेय

सभी जानते हैं कि आजादी के 72 वर्ष बाद भी हमारे देश की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। हमारा देश आज भी गांवों का देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। छोटे-छोटे घरेलू लघु और कुटीर उद्योग ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गांव की पाठशालाएं ही देश के भावी भविष्य का निर्माण करती हैं।

इन सबके बावजूद आजादी से पहले या आजादी मिलने के समय हमारे देश के गांवों की स्थिति और वर्तमान ग्रामीण परिस्थितियों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो काफी बदलाव देखा गया है। आज हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवेश में डिजिटल इंडिया का व्यापक प्रभाव पड़ा है। डिजिटल इंडिया से राष्ट्र निर्माण में ग्रामीणों की सीधी भागीदारी हो रही है। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री ने हमारे देश की ग्रामीण विकास में प्रगति के लिए समस्त देशवासियों को जगाने के लिए डिजिटल इंडिया पर विशेष बल दिया। इसे उम्मीद की किरण दिखने लगी है। इसका सीधा असर बैंकिंग प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी प्रशासनिक अवस्था पर पड़ रही है।

डिजिटल इंडिया ग्रामीण विकास में भारत जैसे विकासशील लोकतांत्रिक देश के लिए एक महत्वपूर्ण जरूरत है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), जिसने सर्वव्यापी ब्रांडबैंड और सबके लिए कम्प्यूटिंग को संभव बनाया है। ग्रामीण विकास में डिजिटल इंडिया निरंतर गतिशील विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह वह विकास है जो देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रहा है।

शहरी और खासकर ग्रामीण इलाकों में ज्ञान की अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के उत्थान में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान है। मोबाइल फोन क्रांति ने हर तबके और क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया है।

डिजिटल इंडिया एक ऐसा लक्ष्य है, जिसकी ओर हमें पूरी ताकत से बढ़ना होगा। 20वीं सदी में जो महत्व बिजली का था, आज 21वीं सदी में वही महत्व इंटरनेट कनेक्शन का है। हम जितनी जल्दी हर व्यक्ति को इंटरनेट से जोड़ सकेंगे, उतना ही देश के लिए बेहतर होगा।

सरकार ग्रामीण विकास के मामले में आम आदमी पर जो जोर दे रही है, उसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को मानव विकास के हर पक्ष के अनिवार्य अंग के रूप में देखना जरूरी है। यह विकास स्वास्थ्य सेवा से शिक्षा तक, सुरक्षा से पर्यावरण संरक्षण तक जुड़ा है। मिसाल के लिए शिक्षा को ही लें, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में आम सोच यही है कि स्कूलों में कुछ कम्प्यूटर लगा दिए जाये और इंतजार किया जाए कि इससे बच्चों की जिंदगी में जादुई परिवर्तन आ जायेगा। इससे काम नहीं चलेगा। उसके लिए समग्रता की सोच लेकर चलना होगा, जिसमें अध्यापक, पाठ्यक्रम, इंटरनेट, पढ़ाई और मूल्यांकन की विधि और माता-पिता को भी शामिल करना अनिवार्य है, ताकि सूचना युग के अभियान तैयार हो सके।

उस प्रक्रिया के लिए पहला जरूरी कदम है, स्कूलों के बुनियादी ढांचे में समयबद्ध सुधार। कुछ अनुमान दर्शाते हैं कि देश में 60 लाख स्कूली

अध्यापकों में से कम से कम 15 प्रतिशत आइसीटी साक्षर हैं। स्वास्थ्य सेवा भी एक अन्य क्षेत्र है, जहां आइसीटी के इस्तेमाल से भारत की प्रतिभा को पहचाना जा सकता है।

मेडिकल पर्यटन भले ही उफान पर हो, लेकिन अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा के कारण हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। हमें इसके लिए ज्यादा डॉक्टरों, अस्पतालों और बिस्तरों की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ ही हमें 10 लाख से भी ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को साधने से युक्त बनाने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को हर भारतीय तक पहुंचाने की ज़रूरत है। दूर से ही रोग के निदान और स्वास्थ्य सेवा (जिसे टेली मेडिसन कहा जा रहा है) की विविध प्रकार के परीक्षणों के जरिए स्थापित किया जा चुका है। कम्प्यूटिंग प्रौद्योगिकी (उच्च क्षमता का पीसीएस) संचार और वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के संगम ने टेलीमेडिसन को वास्तविकता का जामा पहना दिया है।

प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 5-10 लाख रुपये का निवेश परिवर्तन ला सकता है। इसके साथ ही शिक्षा नीति में बदलाव और बजट के आवंटन में 1-2 फीसदी के इजाफे से तीन साल में इस क्षेत्र में चमत्कारिक बदलाव आ सकता है।

सुझाव— देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ई-प्रशासन के प्रयास — जैसे सामुदायिक सेवा केन्द्र (सीएससी) जन्म और मृत्यु प्रमाणीकरण का ऑटोमेशन, एक ही खिड़की पर सभी मामलों के समाधान की व्यवस्था, सूचना घर और ग्रामीण साईबर कैफे आदि— देश भर में लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। इससे ई-कार्यक्रमों की सफलता के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का महत्व भली-भांति समझा जा सकता है। विकास के कार्यक्रम देश में लोगों तक पहुंचाने चाहिए, ताकि ग्रामीणवासी जीवन के उत्तम स्तर का अनुभव पा सकें, चाहे वे कहीं भी हों, उन्हें शहरी क्षेत्र में आने की ज़रूरत न महसूस हो। आज के सूचना युग के विकास के वास्ते कार्यबल तैयार करने के लिए ऐसी समग्र सोच विकसित करने की ज़रूरत है, जिसमें एक ऐसा पाठ्यक्रम शामिल हो, जिसे प्रौद्योगिकी

और इंटरनेट की ताकत हासिल हो।

निष्कर्ष— भारत के लिए विश्व शक्ति बनने का मार्ग तब तक अधूरा है, जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी को सभी पहलू का अनिवार्य अंग बनाने की ज़रूरत है।

गांव के किसान जब सामुदायिक सेवा केंद्र (सीएससी) में इंटरनेट के जरिए फार्म हासिल करता है और शहर तक दौड़ लगाने से बचता है, जो स्वास्थ्य सेवा शहर के अस्पतालों में भीड़ बढ़ने से रोकती है और जीवन की रक्षा करती है और जब हर बच्चा अपनी पसंद की शिक्षा ग्रहण करके रोजगार पाता है तो ये सब लोगों के जीवन स्तर को उठाने में योगदान ही करते हैं। ग्रामीण विकास के जरिए भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दहलीज पर खड़ा है। हम निश्चित ही डिजिटल भारत के पथ पर आगे होंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत में ग्रामीण समाज —डॉ. डी.एस. बघेल
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, संचार के साधन सतत शिक्षा विद्यापीठ 2009
3. प्रसाद अवध 1991, गांवों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन हेतु भीड़िया का योगदान महत्वपूर्ण आलेख रावत पालिकेशन, जयपुर।
4. Devito, A. Josep : Communicology an introduction to the study of communication, Harpeo and Row Publication, New York, 1978
5. Kilvion, J.F. L Communication in India. National Institute of Community Development, Hyderabad, 1978
6. Adal Jogesh : Local communities and National Politics, National Publishing House, New Delhi, 1979.

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 7. | Kuppuswamy, B. : Communication and Social Development in India, Sterling Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1976. | 8. | Desai, A.R. L Rural Sociology In India, Popular Prakashan, Bombay, 1969. |
|----|--|----|--|

